ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4 हल्दी की खेती से किसानों की जेब होगी हेल्दी

रविवारीय, 02 - 08 फरवरी 2020 वर्ष- एक, अंक-26, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 2 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेंट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

क्या ये ग्रामीण भारत का बजट है?

मुख्य संवाददाता

रांची : एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने आम बजट पेश कर दिया और लंबे समय से आ रही परंपरा का निर्वहण करते हुये विपक्ष ने इसे आशाओं पर पानी फेरने वाला कहते हुये इसे पुंजीपतियों के अनुकूल और गरीब विरोधी बताया। हालांकि बजट पेश होते ही शेयर बाजार और सेसेंक्स औंधे मुंह गिर गये जिसे देख विशेषज्ञों ने कहा कि ये देश के गांवों, किसानों और ग्रामीण भारत का बजट है इसी कारण से शेयर बाजार और सेंसेक्स लुढक गये। वहीं सत्ता पक्ष ने इसे एक बेहतरीन बजट कहा है। भारत में बजट की कभी भी तारीफ नहीं होती । हर आम और खास इसे अपने नफे नुकसान के हिसाब से भी तौलता है यही कारण है कि देश का आम बजट कभी भी एक राय नहीं बना पाता। ग्रीन रिवोल्ट ने अपने मूल विषय कृषि , पर्यावरण, जलसंरक्षण के नजरिये से इस बजट को देखा तो इस बजट में किसानों , पशुपालकों,पर्यावरण के लिये कुछ अच्छी खबरें भी हैं, बशर्ते उस पर अमल भी हो?

किसान एक्सप्रेस रेल बहुत कारगर हो सकती है

इस शीतलक युक्त रेल के माध्यम से किसान अपने उपज, दूध, मांस, मछली को अन्य क्षेत्रों में भेज कर बेच सकते हैं। यह प्रयोग अगर सफल रहा तो वास्तव में किसानों को इसका लाभ मिलेगा। अन्यथा जिस प्याज और टमाटर की कीमतें कभी हाहाकारी हो जाती हैं वहीं उपज कभी किसानों को सड़क पर फेंकनी पड़ती है या उसे वो मंडी में ही छोड़ कर चले आते हैं। अब ये देखना जरूरी होगा कि किसान एक्सप्रेस रेल क्या आम किसानों के लिये भी सुलभ हो पायेगा या ये सिर्फ जमींदार टाइप किसानों के लिये होगा?

हवा शुद्ध करने का बजट दसगुणा बढाया गया

दिल्ली में प्रदूषित हवा ने विश्व में हमारी छवि को दागदार बनाया। क्रिकेट मैच तक प्रदूषित हवा और धुंध के कारण रद्द करने पड़े। अब सरकार ने हवा शुद्ध करने का बजट 460 करोड़ से बढा कर 4400 करोड़ कर दिया है। ये तकरीबन दसगुणा वृद्धी है। पर्यावरणविद सरकार की इस घोषणा का स्वागत कर रहे हैं। अपने बजट भाषण में सीतारमण ने कहा, ''10 लाख से बड़ी आबादी वाले नगरों में स्वच्छ हवा चिंता का विषय है। सरकार उन राज्यों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव करती है जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं बना रही हैं और कार्यान्वित कर रही हैं।

लेकिन राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की राशि में हुई कटौती

देश भर की नदियों के संरक्षण के लिये चल रही नदी संरक्षण योजना के लिये वर्तमान बजट में 360 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। वित्तमंत्री ने बजट 2020-21 में राष्ट्रीय गंगा योजना और घाट निर्माण कार्य के लिए बजट में बढ़ोतरी की है लेकिन राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के बजट में बड़ी कटौती कर दी है। राष्ट्रीय गंगा योजना और घाट निर्माण कार्य के लिए अनुमानित बजट 800 करोड़ है। यहां एक तथ्य यह भी है कि पहले भी इस मद मेंबजट में दी गयी राशि को पूरी तरह से खर्च नहीं किया जा सका। यानि हमें देश की नदियों को बचाने और संवारने के क्षेत्र में हमें अभी और काम करने होंगे।

उम्मीदों के विपरीत है केंद्र सरकार का आम बजट : मुख्यमंत्री

- बजट में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं
- गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों और युवाओं की उम्मीदों को बजट से मिली है हताशा
- बजट में नहीं है कोई विजन, उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के हितों का रखा गया है विशेष ध्यान।

मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन ने आम बजट को लोगों की उम्मीदो के विपरीत बताया है। यह बजट गरीब, किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों और युवाओं को हताश करने वाला है। इस बजट का अर्थशास्त्री लगातार आकलन कर रहे हैं। इसके उपरांत ही यह कहा जा सकता है कि इस बजट से देश का कितना विकास होगा.लेकिन, पहली नजर में हमारे दृष्टिकोण से केंद्र सरकार का यह बजट कहीं से विजनरी नहीं लग रहा है।

ट्राइबल यूनिवर्सिटी की मांग की थी, मिला ट्राइबल म्यूजियम

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे प्रधानमंत्री से मिलकर झारखंड में ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने की मांग रखी थी। लेकिन, आज पेश किए गए बजट में रांची में ट्राइबल म्यूजियम खोलने की बात है। इस तरह इस बजट में झारखंड की बहुप्रतीक्षित मांग भी पूरी नहीं की गई और यहां के आदिवासियों के साथ फिर एक बार धोखा दिया गया।

झारखंड में मानव तस्करी के दाग को धोना हमारी पहली प्राथमिकता:मुख्यमंत्री

रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने ट्वीट करके यह कहा है की झारखंड से मानव तस्करी के दाग को धोना सरकार की पहली प्राथमिकता है।गुमला जिले की 06 नाबालिग बेटियों को दिल्ली से मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त कराये जाने के बाद इन्हें मिल रही धमकियों के बाबत मुख्यमंत्री ने गुमला पुलिस को इस मामले को पहली प्राथमिकता में रखते हुए मानव तस्करों को पकड़ने और उन पर कड़ी कार्रवाई करने का निदेश दिया है। उन्होंने गुमला उपायुक्त को क्षेत्र में ऐसे बच्चों की पहचान करने को भी कहा है जो मानव तस्करी का शिकार हो सकते हैं, उन बच्चों को शिक्षा एवं स्किल कार्यक्रम से जोड़ते हुए उनके सतत ट्रैकिंग की व्यवस्था करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने जिला के सीडब्ल्यूसी, डीसीपीओ एवं एंटी-ट्रैफ़िकिंग पुलिस यूनिट को सशक्त और संवेदनशील बनाने का निदेश दिया है ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगायी जा सके।

राहे प्रखंड के बनसिया पंचायत पहुंचे उपविकास आयुक्त रांची ,आमजनों की सुनी

संवाददाता :रांची जिले के सभी 18 प्रखंडों में उपायुक्त रांची राय महिमापत के निदेशानुसार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी प्रखंडों में पंचायतवार आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में नोडल पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान पदाधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्र में आमजनों की समस्याओं को सुना एवं उनके समाधान के लिए आश्वासन दिया। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में रांची जिला के सभी प्रखंडों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 01 फरवरी 2020 को किया गया। इस दौरान प्रखण्डों में ग्रामीण विकास की योनजनाओं, स्वच्छ भारत मिशन, खाद्यान्न सुरक्षा योजना एवं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आमजनों की शिकायतों/समस्याओं को जिला एवं प्रखण्ड स्तर के अधिकारियों ने सुना। जिसके पश्चात संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को समस्या की जानकारी दी गई एवं शिकायतकर्ता को इसके समाधान के प्रति आश्वस्त किया गया।

उप विकास आयुक्त अनन्य मित्तल राहे प्रखंड के बनसिया पंचायत में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पंचायत के लोगों की समस्याओं को सुना एवं उनके समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया। उपविकास आयुक्त ने कहा कि जल्द से जल्द शिकायत का समाधान कर इसकी जानकारी डीडीसी ऑफिस को उपलब्ध करवाएं। बुंडू प्रखंड के चुरगी पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

सांसद/विधायक निधि के लंबित योजनाओं को जल्द करें पूरा : डीडीसी

रांची :उपविकास आयुक्त रांची अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में आज दिनांक 31 जनवरी 2020 को सांसद/विधायक निधि के अन्तर्गत किये गये कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। विकास भवन रांची सभागार में आयोजित बैठक में उपविकास आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ सांसद/विधायक निधि से विभिन्न योजनाओं के अलग-अलग वित्तीय वर्षों में किये गये कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। विधायक निधि के अंतर्गत एनआरईपी-1, एनआरईपी-2 और जिला अभियंता के लंबित योजनाओं की समीक्ष करते हुए उपविकास आयुक्त ने कहा कि योजनाएं क्यों लंबित हैं? संबंधित अधिकारी इस पर ध्यान दें। कुछ योजनाओं के डीसी विपत्र पूरा नहीं होने पर उपविकास आयुक्त ने कहा कि अधिकारी जल्द से जल्द इसकी प्रक्रिया पूरी करें।

विनय रंजन सीसीएल के निदेशक (कार्मिक) के रूप में कार्यभार संभाला

रांची : विनय रंजन ने सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड (सीसीएल) के निदेशक (कार्मिक) के रूप में 24 जनवरी को अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने के बाद सीसीएल मुख्यालय, रांची में अधिकारियों और कर्मियों से मिलें। ज्ञातव्य हो कि अगस्त 2018 से विनय रंजन ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) में भी निदेशक (कार्मिक) के पद पर नियमित रूप से कार्यरत हैं। निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) भोला सिंह ने विनय रंजन से उनके कक्ष में आकर मिले और उन्हें शुभकामनाएं दी।

माणिक शंकर बने वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी

रांची : माणिक मंडल रांची रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी बनाये गये हैं। इन्होंने राँची यूनिवर्सिटी से मैथ्स मे ग्रेजुएशन किया है तथा पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ से एम.बी.ऐ की शिक्षा प्राप्त की है। माणिक मंडल आई.आर.पी.इस 2010 बैच के अधिकारी है तथा आपने सर्वप्रथम वर्ष 2011 मे सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर चक्रधरपुर मंडल मे भारतीय रेलवे मे कार्य शुरू किया।

सीसीएल में 'वाटर कंजरवेशन इन कोल माइंस' पर सेमिनार में बोले जलपुरुष राजेन्द्र सिंह

वाटर इज क्लाईमेट, क्लाईमेट इज वाटर

संवाददाता

रांची :सी.सी.एल. मुख्यालय, रांची के 'कन्वेंशन हॉल' स्थित 'ऑडिटोरियम' में 'वाटर कंजरवेशन इन कोल माइंस' पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेमिनार के मुख्य अतिथि जल पुरूष (मैगसेसे अवार्डी) राजेन्द्र सिंह एवं सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रिकार मधुकर, निदेशक तकनीकी (संचालन) वी.के. श्रीवास्तव, निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) भोला सिंह, निदेशक (वित्त) एन.के. अग्रवाल सहित मुख्यालय के विभिन्न विभागों के महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष एवं बड़ी संख्या में कर्मी उपस्थित थे।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजेन्द्र सिंह ने उपस्थित सभी को संबोधित करते हुए कहा कि वाटर इज क्लाईमेट, क्लाईमेट इज वाटर इस तथ्य को अब सारा विश्व मान रहा है। मुख्य अतिथि ने कहा कि कोल इंडिया को जल साझरता एवं जल के कुशल उपयोग में कौशल विकास पर कार्य करने की आवश्यकता है और मैं आशा करता हूॅ कि प्रबंधन इस पर सकारात्मक पहल करेगा। उन्होंने पावर प्वाइंट प्रजेटेंशन के माध्यम से बताया कि भारत में भूमिगत जल के अत्याधिक दोहन से एक आपातकाल स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसके लिए हम सभी को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने विस्तार से राजस्थान में किये गये कार्यो के बारे में बताया। उन्होंने राजस्थान में किये गये कार्यो के वैज्ञानिक पक्ष को रखते हुये बताया कि किस प्रकार हम जन सहयोग से जल संरक्षण के दिशा में कम से कम खर्च में कार्य कर सकते हैं। उन्होंने सभी को प्रेरित करते हुये कहा कि क्लाईमेट (जलवायू परिवर्तन) को सही दिशा में लाना हम सभी की जिम्मेदारी है।

जलपुरूष राजेंद्र सिंह (दायें) का स्वागत करते सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह

सीएमडी गोपाल सिंह ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुये कहा कि आज हम सभी का सौभाग्य है कि जल पुरूष राजेन्द्र सिंह सीसीएल प्रागंण में आये हैं। सिंह ने बताया कि कोल इंडिया द्वारा राष्ट्र हित में देश की उर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला उत्पादन कर रहा है। आज देश में हर दस में सात बल्ब हमारे कोयले से जलता है परंतु यह भी एक सत्य है कि कंपनी पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान देते हुये इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। सीसीएल, जल पुरूष द्वारा दिये गये सुझाव पर आगे बढ़ते हुये जल साझरता एवं जल के कुशल उपयोग हेतु कौशल विकास पर कार्य करेगा, श्री सिंह ने जोर देते हुये कहा।

इस अवसर पर निदेशक तकनीकी (संचालन) श्री वी.के. श्रीवास्तव, निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना)भोला सिंह, निदेशक (वित्त) श्री एन.के. अग्रवाल ने भी 'वाटर कंजरवेशन इन कोल माइंस' विषय पर संबोधित किया। मंच संचाल वरीय प्रबंधक (वित्त) ए.डी. वाधवा ने किया।

तेजी से गायब हो रहा है मंगल ग्रह से पानी

एजेंसियां :एक अंतरराष्ट्रीय शोध टीम ने खुलासा किया है कि मंगल ग्रह में पानी की मात्रा बड़ी तेजी से कम होती जा रही है

पहले लगाए गए अनुमानों की तुलना में छोटे लाल ग्रह यानी मंगल ग्रह से पानी अधिक तेजी से घट रहा है। एक अंतरराष्ट्रीय शोध टीम ने खुलासा किया है कि मंगल ग्रह के वातावरण (मार्टियन वायुमंडल) से करीब 80 किमी से अधिक की ऊंचाई पर जल वाष्प जितना सोचा नहीं गया था, उससे अधिक अनुपात में जमा हो रहा है। मौसमी परिवर्तनों के दौरान पानी के वाष्प में तेजी से बदलने के कारण मंगल से पानी समाप्त हो सकता है। ग्रहों के क्रम में मंगल, सूर्य से चौथा ग्रह है और सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल को "लाल ग्रह" के रूप में जाना जाता है। मंगल के ऊपरी वातावरण से पानी (एच2ओ) धीरे-धीरे गायब हो रहा है। सूर्य का प्रकाश और रसायन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं में से पानी के अणुओं को अलग कर देते हैं। पानी के ये अणु मंगल के कमजोर गुरुत्वाकर्षण के कारण वहां रुक नहीं पाते है, सीधे अंतरिक्ष में चले जाते हैं। उल्लेखित है कि मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का एक तिहाई 1/3 है।

समरी लाल और बीके विजय को अधिवक्ताओं ने किया सम्मानित

संवाददाता

रांची :कांके विधानसभा क्षेत्र के नव निर्वाचित विधायक समरी लाल एवं सांसद प्रतिनिधि बीके विजय का आज नया बार भवन के प्रथम तल पर अधिवक्ताओं के द्वारा पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक समरी लाल ने कहा कि वह अधिवक्ताओं के हित में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि रांची बार के अधिवक्ताओं की कोई भी समस्या हो, वह समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। विधायक समरी लाल ने अधिवक्ताओं के द्वारा सम्मानित करने पर अधिवक्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। विधायक समरी लाल को सम्मानित करने वालों में अधिवक्ता राजीव रंजन ठाकुर, अजहर अहमद खान,एस एन प्रसाद,पी डी सिंह, रेखा वर्मा, मृत्यंजय प्रसाद,रौशन पासवान, सतेन्द्र सिंह, मृत्यंजय महतो समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित थे।

अंततः पूरी तरह से रोकना हीं होगा पाम ऑयल का आयात

देवाशीष

भारत ने रिफाइंड और प्रसंस्कृत पाम ऑयल के आयात को सीमित किया है। यूरोपीय संघ ने भी परिवहन ईंधन के रूप में पाम ऑयल के इस्तेमाल को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। ये दोनों वैश्विक पाम ऑयल क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने वाले हो सकते हैं। भारत और यूरोपीय संघ इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल के सबसे बड़े आयातक हैं। दुनिया के कुल उत्पादन में इन दोनों देशों की हिस्सेदारी 85 प्रतिशत है।आयात को लेकर भारत के निर्णय पर भले ही मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद की जम्मू कश्मीर तथा नए नागरिकता कानून पर टिप्पणियों का असर हो लेकिन इसकी जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। ऐसा इसलिए ताकि घरेलू खाद्य तेल उद्योग को बचाया जा सके। यूरोपीय संघ का कदम पाम ऑयल की खेती के पर्यावरण संबंधी दुष्प्रभावों से प्रेरित है। इसके चलते वन क्षेत्र में कमी आई और तमाम जीवों का रहवास नष्ट हुआ। इसमें दो राय नहीं कि पाम ऑयल की आपूर्ति करने वाले देश विश्व व्यापार संगठन में इसे चुनौती देंगे लेकिन इसका असर शायद ही हो क्योंकि मामला व्यापार से अधिक पर्यावरण से संबंधित है।

भारत के निर्णय पर भी विश्व व्यापार संगठन की शरण ली जाएगी या नहीं यह अभी तय नहीं है। प्रथम दृष्ट्या लगता नहीं कि इससे किसी स्थापित अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवहार को क्षति पहुंची हो। न तो यह किसी देश से संबंधित है और न ही आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। इसके तहत केवल रिफाइंड पाम ऑयल के आयात के लिए पूर्व अनुमति को आवश्यक किया गया है। बहरहाल, मलेशिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर अवश्य पड़ेगा।पाम ऑयल मलेशिया का सबसे बड़ा कृषि निर्यात उत्पाद है और उसके सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी 2.8 फीसदी है। आश्चर्य नहीं कि मलेशिया कीमतों में रियायत के साथ-साथ पाम ऑयल के बदले भारत से चीनी और भैंसे के मांस के आयात में बेहतर सौदेबाजी पर विचार करे। उधर, इंडोनेशिया को कारोबार बढने से लाभ मिलने की आशा है।भारत की बात करें तो विदेशों से रिफाइंड पाम ऑयल की अबाध आवक रोकने का यह बेहतर अवसर है। मलेशिया नियमित रूप से अपने पाम ऑयल शुल्क ढांचे में बदलाव करता रहता है ताकि रिफाइंड ऑयल के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। इससे भारतीय खाद्य तेल उद्योग को नुकसान पहुंचता है। उसने खाद्य तेल की रिफाइनिंग क्षमता में भारी निवेश किया है लेकिन उसका अधिकांश हिस्सा अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा।औसत क्षमता इस्तेमाल घटकर 46 प्रतिशत रह गया है। कई छोटे और मझोले स्तर की रिफाइनरी बंद हो गई हैं जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सस्ते आयात ने घरेलू खाद्य तेल कीमतों को कम रखा जिसका नुकसान स्थानीय तिलहन किसानों को उठाना पड़ा। घरेलू तिलहन उत्पादन के मांग से तालमेल न बिठा पाने की यह भी एक वजह है।पाम ऑयल की खेती के मामले में अभी भारत में काफी कुछ किया जाना है। इस दिशा में केवल सरकारी प्रोत्साहन से बात नहीं बनेगी क्योंकि जमीन की उपलब्धता और पौधों को तैयार होने में लगने वाला लंबा वक्त भी बाधा है। भारत में अन्य फसलों का उत्पादन बढ़ाने और वृक्ष आधारित तेल की मदद से खाद्य मेल की कमी दूर करने तथा उसे खाद्य प्रसंस्करण, सौंदर्य प्रसाधन और औषधि क्षेत्र में इस्तेमाल करने की पर्याप्त संभावना है। परंतु किसानों द्वारा तिलहन फसलों में निवेश करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए जरूरी है कि लाभकारी कीमत सुनिश्चित की जा सके। आयात को कम करके सस्ते खाद्य तेल की आवक को रोकना इस दिशा में एक कदम साबित हो सकता है।

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

- Repair your laptop with 3-month warranty.

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, ranchi
93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

नदी संरक्षण योजना राशि में कटौती

देश में नदियों की सफाई का कार्यक्रम 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ शुरू हुआ था। 1955 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत गंगा एक्शन प्लान का दायरा दूसरी नदियों तक बढ़ा दिया गया। इस योजना के तहत नदियों में प्रदूषण कम करने का प्रयास किया जाता है। इन प्रयासों में नगरों के सीवेज को सीधे नदियों में डालने से रोकना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, रिवरफ्रंट का विकास, विद्युत शवदाह गृह का निर्माण, लकड़ी के शवदाह गृहों में सुधार आदि शामिल है। योजना का लक्ष्य नदियों के पानी की गुणवत्ता में सुधार करना है। योजना के तहत देश भर के 16 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों- आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु और तेलंगाना में बहने वाली 33 नदियां आती हैं। कुल 77 नगर इस योजना में शामिल हैं।

वर्तमान बजट में 360 करोड़ रुपए की कटौती की गई है वित्तमंत्री ने बजट 2020-21 में राष्ट्रीय गंगा योजना और घाट निर्माण कार्य के लिए बजट में बढ़ोतरी की है लेकिन राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के बजट में बड़ी कटौती कर दी है। राष्ट्रीय गंगा योजना और घाट निर्माण कार्य के लिए अनुमानित बजट 800 करोड़ है। हालांकि सरकार ने बजट 2019-20 में इस कार्य के लिए अनुमानित बजट 750 करोड़ रुपए रखा था लेकिन संशोधित अनुमानों के मुताबिक, सरकार केवल 353 करोड़ ही खर्च कर पाई। मूल सवाल ये है कि इतने सालों से चल रही इन योजनाओं का फल क्या निकला? कुंभ के समय प्रयाग में गंगा के जल को तीर्थयात्रियों ने ज्यादा साफ कहा इस एक उपलब्धि को छोड़ दें तो हमारी ज्यादतर नदियां आज भी प्रदूषित ही हैं और हम अपनी नदियों को साफ करने का सिर्फ शोर करते रहे हैं?

भले नद्दियों के सफाई के बजट में कमी की गयी है लेकिन दो उदाहरण हमें बहुत कुछ कह रहे हैं। जिस पटना के घाटों को गंदगी और प्रदूषण का पर्याय समझा जाता था उसे बिहार सरकार ने अप्रत्याशित रूप से संवार कर साफ सुथरे पर्यटन स्थल में बदल दिया है वहीं रांची में महज कुछ किमी लंगी हरमु नदी को लंदन के थेम्स नदी की तरह संवारने का प्रहसन आज तक चल रहा है और हरमु नदी करोड़ा खर्च करने के बाद भी गंदे नाले के रूप में हमें चिढा रही है। तो ऐसे में बजट में कटौती का रोना रोने से क्या फायदा?

बिना लाइसेंस रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक बेचने वालों पर होगी कार्रवाई

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कहा कि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग को कम करने के लिए बिना लाइसेंस रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों को बेचने वाले डीलर्स और कंपनियों पर कार्रवाई की जाए।

उन्होंने कहा कि ऐसे उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के कारण खराब हुई फसलों के बारे में यदि कोई शिकायत किसानों से प्राप्त होती है तो डीलर्स और कंपनियों के साथ-साथ संबंधित अधिकारी पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा किसान को खराब हुई फसल का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि बिना लाइसेंस रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक बेचने वाले डीलर्स और कंपनियों पर अब तक की गई कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट दी जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि खेती की लागत को कम करने के साथ-साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आमदनी में वृद्धि करना है। इसके अलावा गुरुग्राम जिले में किसानों के लिए ऑर्गेनिक मार्केट भी स्थापित की जाएगी। इस मार्केट के माध्यम से किसान अपने उत्पादों को सीधे बेच सकेंगे। कृषि मंत्री ने वीरवार को पंचकूला में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को डिजिटल किसान बनाने के लिए चैटबॉट लांच किया और उसके बाद कृषि विभाग के मुख्यालय और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की। जेपी दलाल ने बैठक की अध्यक्षता कर कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश देकर कहा कि प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जाए और किसानों को इस बात की जानकारी दी जाए कि सूक्ष्म सिंचाई से न केवल पानी की बचत होती है बल्कि उत्पादकता भी बढ़ती है।

हमें बचाना ही होगा पहाड़ों को

अब दुर्गम पहाड़ियों में पीढ़ियों से रहते आ रहे वहां के निवासी भी स्थायी वास से कतराने लगे हैं। जैव विविधता के सर्वाधिक संकटग्रस्त आधे क्षेत्र पहाड़ों में ही हैं।

वीरेंद्र कुमार पैन्यूली

अंतरराष्ट्रीय पर्वत वर्ष मनाने की शुरुआत 11 दिसंबर, 2002 को न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से की गई थी। साल समाप्त होते-होते 20 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा से यह भी प्रस्ताव पारित हो गया था कि 11 दिसंबर से हर साल अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद अगले साल यानी 2003 में पहला अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया था। इससे पहले पूरे विश्व में पर्वतों और पर्वतवासियों के प्रति चेतना जगाने के लिए 1992 में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण एवं विकास के रियो सम्मेलन में पहली बार यह महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना की गई थी कि भविष्य में पर्वतों का विकास सतत विकास की नीति-रीति के अंतर्गत हो। पर्वतों की सहज भंगुर संवेदनशील पारिस्थितिकीय प्रणालियों और पर्वतीय परिवेश के निवासियों की सामाजिक जीवनयापन की स्थितियों को केंद्र में रख कर ऐसा टिकाऊ विकास कैसे किया जाए, इसका विवरण सतत विकास के एजेंडा-21 के तेरहवें अध्याय में वर्णित है, जो आज भी प्रासंगिक है।

हर साल अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस पर जल और खाद्य आपूर्ति में पर्वतों की भूमिका की स्वाभाविक चर्चा के साथ-साथ यह भी रेखांकित किया जाता है कि विश्व की बारह फीसद आबादी को पर्वतों से सीधा जीवन समर्थक आधार मिलता है, पर्वतीय सामग्रियों, संसाधनों और सेवाओं से दुनिया की लगभग आधी आबादी लाभान्वित होती है और पर्वत समूह विश्व की जल मीनारें होने के साथ-साथ वायु चक्रों, जल व मृदा चक्रों को भी प्रभावित करते हैं। अतः जलवायु परिवर्तन का जो असर पहाड़ों में आएगा, उससे पर्वतों में बसने वाले एक अरब से ज्यादा लोग तो प्रभावित होंगे ही, दुनिया की आधी जनसंख्या भी इसके असर से अछूती नहीं रहेगी। उल्लेखनीय यह भी है कि विश्व को जलवायु बदलाव और उसके प्रभावों के शुरुआती संकेत विश्व के पर्वतों से ही मिले हैं।

पिछले साल 31 अक्तूबर को उच्च पर्वतीय शिखर सम्मेलन के अंत में विश्व मौसम विज्ञान संगठन का भी बयान था कि जलवायु परिवर्तन और विकास के कारण उच्च पर्वतीय इलाकों पर गहराते संकटों को टालने के लिए तुरंत ही वैश्विक कार्यवाही की आवश्यकता है। यहां संकटों का मुख्य संदर्भ पहाड़ों में पिघलती बर्फ और अन्य जल संबंधी खतरों से है। सभी अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवसों पर सार रूप में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों से यही आवाज उठती रही है कि पहाड़ हमारे लिए जरूरी हैं और उन पर तुरंत आवश्यक ध्यान दिए जाने की जरूरत है। अगर पर्वत जरूरी हैं तो उन्हें बचाए रखने के लिए उनकी देखरेख और संरक्षण करना भी हमारी जिम्मेदारी है। दुनिया में पर्वतीय क्षेत्रों में करीब एक अरब लोग रहते हैं। जैव विविधता के सर्वाधिक संकटग्रस्त आधे क्षेत्र पहाड़ों में ही हैं। पहाड़ों का टूटना, दरकना, जलस्रोतों का सूखना, हिमनदों का पिघलना ऐसी मानवजनित गलत विकास नीतियों के साथ-साथ अतिरेकी मौसमी घटनाओं के परिणाम हैं। अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवसों पर हर साल एक मुद्दा विशेष होता है। साल 2017 का विषय पर्वतीय यथार्थों को व्यक्त करता हुआ था। दबाव में पर्वत जलवायु, भुखमरी और पलायन। इसके बाद 2018 का सूत्र विचार पहाड़ों की अपरिहार्यता पर केंद्रित था। अर्थात पहाड़ों का होना महत्त्व रखता है। इस विषय के माध्यम से युवाओं को आपदा जोखिम कम करने, जैव विविधता, जल उपलब्धता, खाद्यान्न और जनजातीय लोगों के लिए पर्वतों का महत्त्व बताना था। पिछले साल यानी 2019 के अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस का विषय सूत्र- 'युवाओं के लिए पर्वत का महत्त्व' रखा गया। निस्संदेह युवा अपने लिए पर्वतों के महत्त्व को जान कर उन पर्वतीय संसाधनों के संरक्षक की जिम्मेदारी निभाने के लिए भी संवेदनशील बन सकते हैं जो जलवायु परिवर्तन के कारण संकट में हैं। परंतु परिवारों के पलायन के साथ युवाओं का पहाड़ों में टिका रहना भी आसान नहीं रह गया है।

अब दुर्गम पहाड़ियों में पीढ़ियों से रहते आ रहे वहां के निवासी भी स्थायी वास से कतराने लगे हैं। जैव विविधता के सर्वाधिक संकटग्रस्त आधे क्षेत्र पहाड़ों में ही हैं। युवा पलायन के कारण स्थानीय ज्ञान धरोहरों में अब अनुभवों और संवेदनाओं से नया जुड़ाव मुश्किल होता चला जाएगा। किंतु जानकारी, ज्ञान में वृद्धि पीढ़ियों के आवास, अधिवास और लगाव से होती है। स्थानीय लोगों को जैव विविधता का ज्ञान, मार्गों का ज्ञान, आपदाओं का ज्ञान, उनसे बचने या उनको झेल कर उबरने का ज्ञान, औषधियों का ज्ञान, स्थानीय खेती, पशुपालन, आवास निर्माण, औषधियों का ज्ञान जो पीढ़ियों से समृद्ध होता आ रहा है, जैसे अनुभव होते हैं जो उन्हें पहाड़ के कठिन जीवन से संघर्ष करना सिखाते हैं। इसी के बूते दुर्गम पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग बाहरी दुनिया से लगभग अलग-थलग पड़ जाने के बाद भी आपदाओं से निपटने और उनसे उबरने की ताकत रखते हैं।वर्तमान पर्वतीय यथार्थ युवाओं के लिए कितना विडंबना भरा है, इसका आभास पहाड़ों पर शोध करने वाली संस्था- आइसीमोड के तत्कालीन महानिदेशक के 2018 के अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस पर दिए गए इस संदेश से मिल जाता है कि 'पर्वत पानी के लिए जरूरी हैं, किंतु ग्लेशियर पीछे खिसक रहे हैं और सोते-जलस्रोत सूख रहे हैं। पहाड़ पर्यटन के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, पर अधिकांश समुदाय उनसे लाभान्वित नहीं होते हैं। वे आपदाओं के जोखिम कम करने में प्रासंगिक हैं, पर स्वयं अनुपात से कहीं ज्यादा जोखिमों का सामना करते हैं। वे भोजन, खाद्यान्न के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, पर उनमें भूमंडल के कुछ सबसे ज्यादा भूखे लोगों का रहना होता है। वे जनजातीय लोगों के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण हैं, किंतु उनमें से अधिकांश को वहां हाशिये में डाल दिया गया है। वे जैव विविधता के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन वहां उनकी कई जातियां, प्रजातियां और उनके अधिवास जोखिम में हैं। वे युवाओं के लिए महत्त्वपूर्ण है, किन्तु कई नौजवान अपने पर्वतीय गांवों को छोड़ कर शहरों की भाग रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोग अब भी रह रहे हैं, उनका एक बड़ा तबका सबसे ज्यादा गरीबी की मार झेलने वाला है। ये लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा में जीने को मजबूर हैं। वन्य जीव और मानव के बीच के टकराव से ग्रामवासियों के पशुपालन, खेती को गंभीर खतरा खड़ा हो गया है और जंगली जानवर का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। फिर प्राकृतिक आपदाएं भी पीछा नहीं छोड़तीं। गर्मी, बारिश और ठंड में बर्फबारी से भूस्खलन और हिमखंडों का गिरना हमेशा का संकट बन गया है। ऐसे में स्वयं पर्वत भी क्षरित व संकट ग्रस्त हो रहे हैं।

जमीनी यथार्थ यह है कि पर्वतों में भौगोलिक कठिनाइयों के बीच भी पीढ़ियों से पहाड़ों में रहने वाले परिवार भी अब गहराते पर्यावरणीय कुप्रभावों और जलवायु परिवर्तन कीआघातजनित समस्याओं से बचने के आसान तरीके खोजने में लगे हैं। इसके लिए सबसे आसान विकल्प अपने-अपने गांव छोड़ कर दूसरे सुरक्षित ठिकानों की तलाश में पलायन है। ऐसे में 2019 में सबसे ज्यादा ध्यान पर्वतों में युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सुविधाओं पर दिया जाना चाहिए, ताकि लोग पलायन को मजबूर न हों। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए दूरगामी रणनीति बनाने की जरूरत है। पर्यटन का विकास हो, लेकिन प्रकृति और पर्यावरण की कीमत पर नहीं, इसका खासतौर से खयाल रखना होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे रोजगार पैदा करने की जरूरत है जो कृषि से इतर हों और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं। इसके लिए युवाओं सहित हर वर्ग की भागीदारी को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि लोग पलायन के बारे में सोचने को मजबूर न हों। लोगों में इस चेतना का विकास करना होगा कि पहाड़ों को बचाना जरूरी है, पहाड़ बचेंगे, तभी प्रकृति भी बच पाएगी और दुनिया आज जिन प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रही है, उन्हें रोकने में मदद मिल सकेगी।

कीटनाशकों के मकड़जाल में फंस चुके है हम

अखिलेश आर्येंदु

ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि कीटनाशक बच्चों के दिमाग को घुन की तरह खोखला कर रहे हैं। बच्चों के मानसिक विकास पर कीटनाशकों के प्रभाव के अध्ययन में यह सामने आया कि देश के कई राज्यों में कीटनाशकों का इस्तेमाल सरकार द्वारा निर्धारित वैज्ञानिक मापदंडों के अनुरूप नहीं है। कंपनियां इनका इस्तेमाल मनमानी तरीके से कर रही हैं, जिससे बच्चों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

अध्ययन में यह सामने आया कि देश के कई राज्यों में कीटनाशकों का इस्तेमाल सरकार द्वारा निर्धारित वैज्ञानिक मापदंडों के अनुरूप नहीं है। ऐसा कई बार हो चुका है जब विशेषज्ञों और जांच प्रयोगशालाओं ने शीतल पेय पदार्थों में जहरीले रसायन होने की पुष्टि की है। लेकिन लगता है कि इस पर केंद्र और राज्य सरकारों ने गौर नहीं किया। यदि हम ध्यान से अंग्रेजी भाषा में कोक और पेप्सी की बोतलों पर लिखे निर्देश पढ़ें, तो उसमें स्पष्ट लिखा है- इसे बच्चों और किशोरों को पीने के लिए न दें, क्योंकि यह उनके लिए उपयुक्त नहीं है। कोक, पेप्सी या अन्य दूसरे पेयों की बोतलों पर ही नहीं, बल्कि दूसरे पेय पदार्थों की बोतलों पर भी इसी तरह के निर्देश लिखे होते हैं। क्या हम कभी उस पर गौर करते हैं? इतना ही नहीं, मैगी सहित जब कई अन्य खाद्य वस्तुओं में मानक से ज्यादा कीटनाशक होने का मामला सामने आया था, तब लोगों को पता चला कि वे एक बेहतरीन खाद्य की जगह जहरबुझे खाद्य का सेवन कर रहे थे। संवेदनहीनता की ऐसी घटनाएं शायद ही दुनिया में और कहीं देखने-सुनने में आएं। पिछले पंद्रह वर्षों में कई बार पेय पदार्थों और मैगी सहित दूसरे खाद्यों में जहरीले पदार्थों की मिलावट की बातें मीडिया में जोर-शोर से उछलीं, लेकिन कुछ ही महीनों में उनकी चर्चा वैसे ही आम लोगों से गायब हो गई, जैसे दूसरी चर्चित घटनाएं।

पानी और भोजन की शुद्धता के नाम पर रासायनिक जहरीले तत्त्वों की जो मात्रा इस्तेमाल की जा रही है, वह बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि बड़ों के लिए भी बेहद नुकसानदायक है। जैसे-जैसे वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और उत्पादन बढ़ रहा है, वैसे-वैसे खाद्यान्नों के भंडार गृहों और खेतों में चूहों और अन्य कीट-पतंगों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। इससे हर साल ग्यारह हजार करोड़ रुपए के कृषि उत्पाद, फल और मेवे नष्ट हो जाते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोकने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर कीनाशकों का इस्तेमाल होता है। गौरतलब है, चूहों और कीटों की रोकथाम के लिए देशी तरीकों को अपनाकर महफूज रहा जा सकता है। एक आंकड़े के मुताबिक 1950 में कृषि उत्पादों और अन्य उत्पादों को बचाने के लिए दो हजार टन कीटनाशकों का इस्तेमाल किया गया था। अब इसकी खपत बढ़ कर चौरानवे हजार टन हो गई है, यानी बहत्तर सालों में परच्यानवे हजार टन कीटनाशकों का उपयोग बढ़ा है।

अब तो शायद ही कोई ऐसी चीज हो, जिसको सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशकों का उपयोग न किया जाता हो। अपवाद के रूप में जैविक खेती के उत्पादों को छोड़ दिया जाए तो, पीने और खाने की हर वस्तु में कीटनाशक मिलाए जाते हैं। आज देश का सारा पर्यावरण कीटनाशकों के इस्तेमाल से जहरीला हो गया है। एम्स के फार्माकोलॉजी विभाग के एक अध्ययन के अनुसार घरों में मच्छर और कॉकरोच मारने के लिए छिड़के जाने वाले कीटनाशकों का चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर असर बहुत घातक असर पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि घर में ही बच्चे जाने-अनजाने में कीटनाशकों की चपेट में आते जा रहे हैं। बिडंबना तो यह है कि शिक्षित घरों में भी इसके प्रति कोई खास जागरूकता नहीं है। घरों में मंहगे-चमकीले सेब, केले, आम, बैंगन, भिंडी, लौकी, नेनुआ जैसी इस्तेमाल होने वाली तमाम सब्जियों में कीटनाशकों का इस्तेमाल, एक नहीं, दो-तीन स्तरीय होने लगा है। खेत में जहां इनका उपयोग फसल बढ़ाने के लिए किया जाता है, वहीं रोगों से बचाव के लिए भी इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। फिर इन्हें चमकदार बनाने के लिए फोलिडज नामक रसायन में डुबोया जाता है। सोचा जा सकता है कि इन तीन स्तरों पर कीटनाशकों और रसायनों के इस्तेमाल से जीवन, पर्यावरण, जैव विविधता और जिस जमीन पर इन्हें उगाया जाता है, उन पर कितना असर पड़ता होगा? एक आंकड़े के मुताबिक 2013-14 में देश में नब्बे लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन में कीटनाशक छिड़के गए थे, 2017-18 में चौरानवे लाख हेक्टेयर जमीन में इनका इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा बागवानी और औषधीय खेती में भी कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, जिससे कोई भी फल पूरी तरह जहरीले रसायनों से सुरक्षित नहीं रह गया है।

उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे अनेक राज्यों में टमाटर की अनेक किस्मों की फसलें उगाई जाती हैं। इन किस्मों में रश्मि और रूपाली प्रमुख हैं। खाने में इनका स्वाद भी अच्छा होता है। लेकिन इन पर हेल्योशिस आर्मिजरा नामक कीड़ा इन्हें बहुत नुकसान पहुंचाता है, यह टमाटर में सुराख कर देता है। इस कीड़े की रोकथाम के लिए बाजार में कई तरह की दवाएं मौजूद हैं, जिनमें रेपलीन, चैलेंजर, रोगर हाल्ट प्रमुख हैं। इनका छिड़काव कई चरणों में किया जाता है। दो साल पहले पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण के राज्यों में कपास की फसल पर सफेद मक्खियों के लाइलाज हमले का मुख्य कारण इन पर अंधाधुंध कीटनाशक छिड़के गए हैं। इससे जहां जमीन में जहर घुलता जा रहा है, वहीं जीवन, पर्यावरण, जैविक विविधता को भी नुकसान पहुंच रहा है। एक शोध के मुताबिक जिन क्षेत्रों की फसलों में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग अधिक किया जाता है, वहां पिछले पचास सालों में कई वनस्पतियां और कीट-पतंगे हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं। देश में कई ऐसे इलाके हैं, जहां कीटनाशकों की गंध के कारण सारा वातावरण जहरीला बनता जा रहा है और सांस, त्वचा, दिल और दिमाग संबंधी तमाम बीमारियां आमतौर पर होने लगी हैं। विशेषकर हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली के इलाके पर्यावरण के नजरिए से पूरी तरह खराब हो गए हैं।

देश के जानेमाने वैज्ञानिक, पर्यावरणविद् और चिकित्सकों के अनुसार कीटनाशकों से छिड़काव किए गए टमाटर, बैंगन और सेब आदि खाने से किडनी, छाती, स्नायुतंत्र, पाचन अंग और मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ने लगा है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हम कीटनाशकों के मकड़जाल में किस तरह फंसते जा रहे हैं। आज तो स्थिति यह हो गई है कि परिवार के परिवार अब समस्या यह है कि यदि कीटनाशकों का इस्तेमाल न करें तो फसलों और फलों के उत्पादन पर फर्क पड़ता है और यदि करें तो कई समस्याए व रोग बढ़ रहे हैं। फिर बीच का रास्ता क्या है? वैज्ञानिकों के अनुसार देश में इसका समाधान जैविक खेती और जैविक बागवानी है। लेकिन इसे पूरे देश को अपनाने की जरूरत है। जब तक देशभर में जैविक खेती की वरीयता नहीं दी जाएगी, तब तक कीटनाशकों से होने वाली समस्याओं से निजात नहीं पाई जा सकती।

हवा साफ करने का बजट दसगुणा बढा

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए 4,400 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। यह राशि उन शहरों पर खर्च होगी जहां की आबादी 10 लाख से अधिक है। पिछले बजट में इस मद में 460 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए थे। वर्तमान बजट में इसके लिए करीब 10 गुणा बजट बढ़ाया गया है। पर्यावरणविद सरकार की इस घोषणा का स्वागत कर रहे हैं। अपने बजट भाषण में सीतारमण ने कहा, ''10 लाख से बड़ी आबादी वाले नगरों में स्वच्छ हवा चिंता का विषय है। सरकार उन राज्यों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव करती है जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं बना रही हैं और उन्हें कार्यान्वित कर रही हैं। इस प्रोत्साहन के मानदंड पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।''

नेशनल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल में एयर क्वॉलिटी एंड क्लाइमेट रेजीलिएंस कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे पोलाश मुखर्जी ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। हालांकि उनका कहना है कि पटना में यह काम करने के लिए 3,500 करोड़ रुपए की जरूरत है। पोलाश बताते हैं कि भारत में 84 ऐसे शहर हैं जहां की आबादी 10 लाख से अधिक है। यहां प्रदूषण की रोकथाम के लिए बचाव के उपाय करने की जरूरत है।

ऑस्ट्रेलिया के जंगली आग से कार्बन का स्तर आठ लाख साल में सबसे अधिक

ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम के जंगलों में लगी आग ने सिर्फ करोड़ो वन्य जीवों को ही खत्म नहीं किया है बल्कि इसकी भूमिका वर्ष 2020 में कार्बन उत्सर्जन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने में सबसे अहम होगी। पर्यावरण में कार्बन का स्तर पहले ही आठ लाख साल में सबसे अधिक है और इसके तीस लाख साल के उच्चतम स्तर पर पंहुचने का अनुमान है। ब्रिटेन के मौसम कार्यालय ने शुक्रवार को यह दावा किया। मौसम विभाग ने कहा कि धरती को गर्म करने के लिए जिम्मेदार कार्बन डाइ ऑक्साइड (सीओ-2) के उत्सर्जन को वर्ष 1958 से दर्ज किया जा रहा है और अनुमान है कि इस वर्ष सीओ्-2 का सबसे अधिक उत्सर्जन होगा।

कोयले चलित संयत्रों को जल्द बंद करेगा जर्मनी

मुरलीधर

जनता और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के दबाव के चलते जर्मनी ने भूरे कोयले से चलने वाले बिजली घरों को पूरी तरह बंद करने की अंतिम समय सीमा और घटा दी है। जर्मनी ने अब 2035 तक ही कोयले को इतिहास बनाने की विस्तृत योजना बना ली है।

राजधानी बर्लिन में पत्रकारों से बातचीत में जर्मनी की पर्यावरण मंत्री स्वेन्या शुल्त्से ने कहा, "कोयले से बाहर निकलना अभी से शुरू हो रहा है और यह करना ही है। पहले 2038 तक कोयला आधारित पावर प्लांटों को पूरी तरह बंद करने की बात कही गई थी लेकिन अब इसे तीन साल और जल्दी पूरा करने की योजना है। जर्मनी की चांसलर अंगेला मैर्केल और चार जर्मन राज्यों के प्रमुखों ने मिलकर उनके यहां चल रहे बिजली घरों के शटडाउन प्लान पर सहमति बना ली है। यह राज्य हैं - सैक्सोनी-आनहाल्ट, सैक्सोनी, नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया और ब्रांडेनबुर्ग। इन चारों राज्यों को पूरी योजना के दौरान 44।7 अरब डॉलर दिए जाएंगे।इस पूरी योजना को एक कानून के मसौदे के रूप में लिखा जाएगा । इस बीच सरकार ने साल 2020 में बंद होने जा रहे कोयला आधारित बिजली घर चलाने वाली कंपनियों को 4।35 अरब यूरो का मुआवजा देने की घोषणा की है। जर्मन वित्त मंत्री ओलाफ शोल्त्स ने कहा है कि यह भुगतान "बंद होने के 15 सालों तक किश्तों में दिया जाएगा। इस मुआवजे का बड़ा हिस्सा नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया में कोयला आधारित पावर प्लांट चलाने वाली एक बड़ी कंपनी आरडब्ल्यूई को मिलना है। कंपनी को 2।6 अरब यूरो मिलने हैं जबकि उसने खुद करीब 3।5 अरब यूरो के नुकसान का अनुमान लगाया है। इस ऊर्जा कंपनी में कम से कम 3,000 नौकरियां खत्म होंगी और 2020 तक समय से पहले रिटायर होने वालों को मिलाकर करीब 6,000 नौकरियां जाएंगी। यह इस कंपनी के कुल वर्कफोर्स का करीब 60 फीसदी हिस्सा है। ये लोग ज्यादातर भूरे कोयले से जुड़े काम में लगे थे। कमोबेश ऐसा ही हाल ज्यादातर कंपनियों का है।

जर्मनी में सामान्य कोयले से चलने वाले पावर स्टेशनों को बंद करने का काम पहले से ही जारी है। अब इस नए पैकेज में भूरे कोयले यानि लिग्नाइट को भी शामिल कर लिया जाएगा। कोयले की इस सबसे प्रदूषक किस्म लिग्नाइट का जर्मनी सबसे बड़ा उत्पादक है और इससे देश की करीब 19 फीसदी बिजली बनाई जाती है।

सन 2038 तक कोयला वाले प्लांटों को बंद करने की बात करीब एक साल से चल रही थी। लेकिन पर्यावरण कार्यकर्ताओं के दबाव बनाने से उसे तीन साल और कम कर दिया गया है। इस कदम को भी नाकाफी बताते हुए भूरे कोयले का विरोध करने वाले एक गुट एंडेगेलैंडे ने ट्वीट में लिखाः कोयला छोड़ने के रास्ते में कोई तकनीकी अड़चन नहीं है। यह सीधे सीधे राजनीतिक इच्छाशक्ति का सवाल है।2035 भी बहुत लेट है! पहले इस योजना से भूरे कोयले को बाहर रखा गया था लेकिन अब पहली बार विस्तार से बताया गया है कि कब और कैसे कैसे भूरे कोयले से चलने वाले प्लांटों को बंद किया जाएगा। इसके अलावा योजना में प्राचीन हामबाख जंगल को काटे जाने पर भी रोक लगाना भी शामिल है जो एक तरह से जर्मनी के कोयला-विरोधी आंदोलन का प्रतीक बन गया था। जर्मनी पहले ही फैसला कर चुका है कि साल 2022 तक ही परमाणु ऊर्जा से चलने वाले बिजली घरों को भी बंद कर दिया जाना है। देश की कुल बिजली आपूर्ति में फिलहाल एक तिहाई हिस्सा परमाणु ऊर्जा वाले बिजली घरों से ही आता है। कोयला जैसे जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कभी कभी संक्रमण काल के दौरान ही किया जाता है। इस तरह जर्मनी दुनिया का पहला देश बन सकता है जो बिजली बनाने के लिए परमाणु और कोयले से मिलने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करता। ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन घटाने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जर्मनी उन परियोजनाओं को बंद करने के अलावा अक्षय ऊर्जा में बहुत भारी निवेश करेगा।

गुड्डू भारती पहले प्रयास में ही सीए बने

रांची :द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा नवम्बर, 2019 में आयोजित सीए फाईनल परीक्षा में गुड्डू भारती ने रांची शहर में पांचवा स्थान प्राप्त कर अपने माता-पिता के साथ-साथ झारखंड राज्य का नाम रौशन किया है। ज्ञातव्य हो कि गुड्डू भारती के पिता सीसीएल दरभंगा हाउस, रांची में सुरक्षा विभाग में कार्यरत हैं। गुड्डू भारती अपनी सफलता का श्रेय माता श्रीमती पुनम भारती पिता श्री शम्भु दयाल भारती के साथ-साथ गुरूजनों को भी देते हैं।

सीएमपीडीआई परिवार के 10 सदस्यों को भावभीनी विदाई दी गई

रांची : सीएमपीडीआई परिवार के 10 सदस्यों को आज संस्थान के ''कांफ्रेंस हॉल'' में आयोजित एक समारोह में भावभीनी विदाई दी गई। इनमें नवल किशोर-महाप्रबंधक (ईएंडएम), वी0के0 प्रसाद-महाप्रबंधक (ईएंडटी/एमई), सत्येन्द्र हर्ष-मुख्य प्रबंधक (ईएंडएम), एस0के0 सिन्हा-मुख्य प्रबंधक (उत्खनन), एन0पी0 श्रीवास्तव-मुख्य प्रबंधक (भूविज्ञान), संतोष कुमार सिन्हा-अभियंत्रण सहायक, श्रीकांत तिवारी-कार्यालय अधीक्षक, महावीर हजाम-डुप्लीकेटर ऑपरेटर, मुन्ना राम-बेयरर एवं संजीवन उरांव-सहायक सुरक्षा सह इंस्पेक्टर शामिल हैं। इस मौके पर सीएमपीडीआई के महाप्रबंधक (ओपेनकास्ट) दीपांकर भट्टाचार्या एवं महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) श्रीमती सुनीता मेहता ने सेवानिवृत्त कर्मियों को पुष्पगुच्छ, मान-पत्र, प्रतीक चिह्न व शॉल देकर कम्पनी की ओर सम्मानित किया। इस अवसर पर सीएमपीडीआई के महाप्रबंधक दीपांकर भट्टाचार्या एवं महाप्रबंधक श्रीमती सुनीता मेहता ने सभी सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य, सुखी एवं दीर्घायु जीवन की कामना की।

उपायुक्त ने की विधायक निधि कोष की बैठक

- **विधायक/विधायक प्रतिनिधि हुए शामिल**
- **अनुशंसित, स्वीकृत और लंबित योजनाओं पर हुई चर्चा**

रांची :01 फरवरी 2020 को रांची समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में विधायक निधि फंड की बैठक आयोजित की गयी। उपायुक्त रांची राय महिमापत रे की अध्यक्षता में हुई बैठक में उपविकास आयुक्त अनन्य मित्तल, कांके विधायक समरीलाल, खिजरी विधायक राजेश कच्छप एवं अन्य विधायक प्रतिनिधि उपस्थित हुए। बैठक में उपायुक्त ने विधायकों और विधायक प्रतिनिधियों से विधायकों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में अनुशंसित, स्वीकृत और लंबित योजनाओं पर चर्चा की। उपायुक्त रांची रे ने कहा कि विधायक नये योजनाओं के चयन में ये ध्यान रखें कि वो योजना पहले से नहीं ली गयी हो। उन्होंने कहा कि विधायकों और विधायक प्रतिनिधियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें ताकि योजनाओं और इससे संबंधित जानकारी से सभी अपडेट हो सके। विधायकों और विधायक प्रतिनिधियों से उपायुक्त ने कहा कि योजनाओं को लेकर किसी तरह की समस्या है तो वो बतायें। बैठक में उपविकास आयुक्त अनन्य मित्तल ने विधायकों/विधायक प्रतिनिधियों से कहा कि वो प्रोजेक्ट मॉनटरिंग यूनिट (पीएमयू) से दिये गये स्कीम पर भी विचार कर सकते हैं। जन जल योजना के लिए विधायकों/विधायक प्रतिनिधियों को बताया गया कि इस योजना के तहत जो भी राशि खर्च की जायेगी उसका एस्टीमेट ग्रामीण इलाके में पीएचईडी और शहरी क्षेत्र में नगर निगम के हिसाब से लें। उपविकास आयुक्त द्वारा बैठक में विधायकों/विधायक प्रतिनिधियों को बताया गया कि अगर वो अपने क्षेत्र में किसी संगठन या एनजीओ को वाहन देते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि संगठन/एनजीओ का कार्यालय उनके क्षेत्र में हो और वाहनों के क्रय की प्रक्रिया जेम पोर्टल से की जायेगी।

सीएमपीडीआई ने 8.91 लाख मीटर ड्रिलिंग का लक्ष्य प्राप्त किया

रांची : वित्तीय वर्ष 2019-20 में 14 लाख मीटर ड्रिलिंग के एमओयू के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर माह तक 8.91 लाख मीटर ड्रिलिंग का लक्ष्य प्राप्त किया है तथा हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। 26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के पश्चात अपने अभिभाषण में उक्त बातें सीएमपीडीआई के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एस0 सरन ने कही। इस अवसर पर निदेशक (तकनीकी/आरडीएंडटी/सीआरडी) आर0एन0 झा, मुख्य सतर्कता अधिकारी सुमीत कुमार सिन्हा सहित बड़ी संख्या में सीएमपीडीआई परिवार के सदस्य उपस्थित थे। एस सरन ने कहा कि सरकार द्वारा सराहनीय सहयोग प्राप्त हो रहा है। भारत सरकार सीएमपीडीआई को सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के तहत अगले वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 700 करोड़ की निधि उपलब्ध करा रही है ताकि तेजी से गवेषण कर आवश्यक डाटा के साथ कोल ब्लॉक को मंत्रालय को उपलब्ध कराकर उसके विकास हेतु आवंटित किया जा सके।

एस्ट्रोटर्फ हॉकी कैंप का उद्घाटन

संवाददाता

रांची: 27 जनवरी को हटिया स्थित सेरसा एस्ट्रोट्र्फ़ हॉकि स्टेडियम में मण्डल रेल प्रबन्धक नीरज अंबष्ठ ने हॉकि कैंप का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन शक्ति वाहिनी संस्थान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका कॉनसोलेट एवं दक्षिण पूर्व रेलवे, रांची मण्डल के सहभागिता से किया जा रहा है। इस कैंप में 12 से 18 वर्ष आयु की लगभग 110 लड़कियां झारखंड राज्य के विभिन ज़िलो जैसे सिमडेगा, खूंटी, गुमला ,लोहरदगा, चाईबासा आदि से भाग ले रही है। हॉकी कैंप का उद्देश्य उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना, आदिवासी लड़कियों को सशक्त बनाना, नेतृत्व करने की क्षमता को बढ़ावा देना, तथा शिक्षा एवं शैक्षिक अवसरों को बढ़ाना है। यह कैंप लड़कियों के लिए अपने खेल कौशल मे सुधार तथा और बेहतर करने का सुनहरा अवसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिडलबरी कॉलेज की हेड कोच मिस कैथरिन डेलोरेंज़ो एवं मिस रेचल पलुम्बो के मार्गदर्शन मे 11 महिला कोचों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस अवसर पर अपर मण्डल रेल प्रबन्धक एम एम पंडित, अपर मण्डल रेल प्रबन्धक अजित सिंह यादव, वरिष्ठ मण्डल अभियंता अमित कंचन, वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबन्धक सह मुख्य जन संपर्क अधिकारी नीरज कुमार एवं मण्डल के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

वीर शहीदों के सम्मान में श्रद्धांजली

रांची :भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुती देने वाले शहीदों की स्मृति में 30 जनवरी, 2020 को सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड (सीसीएल) में दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजली अर्पित की गयी। मुख्यालय के सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने 11 बजे से 11.02 मिनट तक अपने दैनिक कार्यालीन कार्य को स्थगित कर दो मिनट का मौन रखकर वीर शहीदों को उनके स्वर्णिम बलिदान के लिए श्रद्धांजली अर्पित किया गया।

दुर्घटना संभावित चौराहों की पहचान के लिए बनाई नई तकनीक

एजेंसियां : शोधकर्ताओं ने पीईटी के आधार पर भी वाहनों के टकराने की घटनाओं का अध्ययन किया है। सड़क पर दुर्घटना की आशंका वाले बिंदु से होकर गुजरने वाले वाहनों के बीच समय के अंतर को पीईटी कहते हैं दो शहरों को जोड़ने वाले राजमार्गों पर पड़ने वाले चौराहों पर वाहनों के टकराने के मामले प्रायः अधिक देखे गए हैं। भारतीय शोधकर्ताओं ने अब एक ऐसी पद्धति पेश की है, जो राजमार्गों पर दुर्घटना की आशंका वाले चौराहों की पहचान करने में मददगार हो सकती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि दुर्घटनाओं के खतरे से ग्रस्त चौराहों की पहचान करके उनमें व्यापक सुधार किए जा सकते हैं और सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है।

यह अध्ययन ट्रैफिक में सड़क उपयोगकर्ताओं की धारणा और उसके अनुसार प्रतिक्रिया में लगने वाले समय पर आधारित है। तकनीकी भाषा में इसे पर्सेप्शन-रिएक्शन टाइम कहते हैं, जो दुर्घटना के क्षणों में सड़क उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। खराब सड़क या किसी अन्य आपात स्थिति में वाहन धीमा करना या फिर अचानक ब्रेक मारना सड़क उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया के ऐसे ही कुछेक उदाहरण कहे जा सकते हैं। इसके साथ ही, शोधकर्ताओं ने पोस्ट एन्क्रोचमेंट टाइम (पीईटी) के आधार पर भी वाहनों के टकराने की घटनाओं का अध्ययन किया है। सड़क पर दुर्घटना की आशंका वाले बिंदु से होकर गुजरने वाले वाहनों के बीच समय के अंतर को पीईटी कहते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि पीईटी मूल्य कम होने पर वाहनों के टकराने का खतरा अधिक होता है। ऐसे सिग्नल रहित चौराहों को इस अध्ययन में शामिल किया गया है, जहां पिछले पांच वर्षों में दाएं मुड़ने के दौरान वाहनों के टकराने की सर्वाधिक घटनाएं हुई हैं। चौराहों पर लगे वीडियो कैमरों की मदद से ट्रैफिक संबंधी आंकड़े प्राप्त किए गए हैं और फिर उनका विश्लेषण किया गया है। रिकॉर्ड किए गए वीडियो की मदद से बड़ी और छोटी सड़कों से गुजरने वाले वाहनों के विस्तार, सड़क पर उनके संयोजन और इंटरैक्शन के बारे में वाहनों की जानकारी एकत्र की गई है। अध्ययन में उपयोग किए गए वीडियो आधारित आंकड़े केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के अनुदान पर आधारित भारतीय राजमार्गों पर केंद्रित एक शोध परियोजना इंडो-एचसीएम से प्राप्त किए गए हैं।अध्ययन से पता चला है कि चौराहों पर वाहनों के टकराने की अधिकतर घटनाएं दोपहिया और हल्के व्यावसायिक वाहनों के गुजरने के दौरान देखी गई हैं। दोपहिया वाहनों का आकार छोटा होने के कारण अन्य वाहन चालक ट्रैफिक नियमों को नजरअंदाज करते उन्हें ओवरटेक करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण चौराहों पर दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह उभरकर आयी है कि दूसरे सड़क जंक्शन रूपों की तुलना में चार मार्गों को जोड़ने वाले चौराहों पर वाहनों के टकराने की घटनाएं सबसे अधिक होती हैं। यह नई पद्धति वाहनों के टकराने की आशंका से ग्रस्त चौराहों पर ज्यामितीय डिजाइन में संशोधन जैसे इंजीनियरिंग उपायों, ट्रैफिक नियंत्रण एवं प्रबंधन तकनीकों के कार्यान्वयन के बारे में निर्णय लेने में उपयोगी हो सकती है। इस तरह, सार्वजनिक धन का तर्कसंगत एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने में भी मदद मिल सकती है।

भूकंप से नुकसान रोकने के लिये सरकार कराएगी शहरों की माइक्रो-मैपिंग

भूकंपों को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन क्या उच्च तीव्रता के भूकंपों के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए कोई उपाय है? शायद हां, कम से कम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) कुछ ऐसा ही सोचता है। एक महत्वकांक्षी परियोजना के अंतर्गत मंत्रालय भूकंप के खतरे से ग्रस्त जोन-4 और जोन-5 में शामिल क्षेत्रों की माइक्रो-मैपिंग कर रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भूकंप रोधी शहरों के विकास और अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्रों में इमारतों की सुरक्षा एवं जान-माल के नुकसान को कम करने में इस तरह की मैपिंग उपयोगी हो सकती है। मंत्रालय की योजना के अनुसार, भूकंप के प्रति संवेदनशील शहरों में भूकंप के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के उद्देश्य से इन शहरों की माइक्रो-मैपिंग चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। अब तक सिक्किम के साथ-साथ दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, जबलपुर, अहमदाबाद, गांधीधाम, बंगलौर और देहरादून समेत आठ शहरों की माइक्रो-मैपिंग की जा चुकी है।

महावाणिज्य दूत, अमेरिका ने सीएमपीडीआई का दौरा किया

संवाददाता

रांची : पैटंसिया हॉफमैन, महावाणिज्य दूत, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने सीएमपीडीआई का दौरा किया तथा 2008 से यूएसईपीए के सहयोग से कार्यरत इंडिया सीएमएम/सीबीएम क्लीयरिंग हाउस के कार्यों का निरीक्षण किया। सीएमपीडीआई के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एस0 सरन ने एक बैठक की अध्यक्षता की जिसमें सभी विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। सीएमपीडीआई, सीएमएम/सीबीएम क्लीयरिंग हाउस की उपलब्धि, वर्ष 2023-24 तक 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित योजना तथा कोयला उद्योग के विकास के लिए भावी योजना पर संक्षिप्त प्रस्तुति दी गई तथा इस पर विचार-विमर्श किया और दौरे पर आयी टीम को तकनीकी विवरण के बारे में विस्तार से बताया गया।मौके पर सुश्री पैटंसिया हॉफमैन ने सीएमपीडीआई/सीआईएल को कोयला खनन, सीएमएम/सीबीएम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से संभावित डेवलपर के सहयोग से अन्य संबंधित क्षेत्रों में अपने कार्यालय की ओर से हर प्रकार की सहायता देने का आश्वासन दिया।

सीसीएल में सेवानिवृत कर्मियों को भावभीनी विदाई

रांची :सीसीएल मुख्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मियों सर्वश्री राम विनय सिंह, महाप्रबंधक (खनन), संचालन/उत्पादन विभाग; प्रमोद कुमार सिंह, मुख्य प्रबंधक (वित्त), आंतरिक अंकेक्षण विभाग; बिनोद कुमार सुमन, मुख्य प्रबंधक (ई एंड एम), प्रेस मुख्यालय विभाग; प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, उप प्रबंधक (वित्त), आंतरिक अंकेक्षण विभाग; शिव दयाल कमार, अधीनस्थ इंजीनियर (ई एण्ड एम), ई एण्ड एम-नगर प्रशासन विभाग; सुनील कुमार सिन्हा, वरीय निजी सहायक, ग्रेड 1, सतर्कता विभाग; दीपेन्द्र नारायण घोष, अकांउटेंट ए-1, सीएमपीएफ विभाग; सबीता शरण शर्मा, कार्यालय अधीक्षक, ग्रेड ए-1, वित्त (मुख्यालय) विभाग; पोलीकार्प होरो, कार्यालय अधीक्षक, ग्रेड ए-1, निदेशक के सचिवालय; शिवेन्द्र नारायण गुहा, अकाउंटेंट, ए-1, वित्त विभाग; उदय शंकर ठाकुर, वरीय केमिस्ट, गुणवत्ता नियंत्रण विभाग; मिथलेश कुमार मिश्रा, वरीय सैनीटरी इंस्पेक्टर, नगर प्रशासन विभाग; जीवन कुमार सोनी, उच्च वरीय लिपिक, पी एंड आई आर विभाग; मदन मोहन, टेक्निकल इंस्पेक्टर, गुणवत्ता नियंत्रण विभाग; छत्रि उरांव, ड्राईवर एवं मैकेनिक, सामान्य प्रशासन विभाग; श्रीमती जलेमुन निशा, जिल्दसाज, कर्मचारी स्थापना विभाग; श्रीमती ईलिस बेज, प्यून, आंतरिक अंकेक्षण विभाग; राजेश्वर राम हेड प्यून, निदेशक (वित्त) के सचिवालय तथा केन्द्रीय अस्पताल गांधीनगर से योगेश्वर ठाकुर, इंस्पेक्टर मलेरिया को आज सीसीएल परिवार की ओर से सीसीएल मुख्यालय में ''सम्मान समारोह'' का आयोजन कर भावभीनी विदाई दी गई। मुख्यालय, रांची में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि सीसीएल के निदेशक तकनीकी (संचालन) वी.के. श्रीवास्तव ने उपस्थित कंपनी के वरिष्ठतम सेवानिवृत कर्मियों का अभिनंदन एवं स्वागत किया तथा सभी का पुष्पमाला, पुष्पगुच्छ, शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह, सम्मान पत्र, धार्मिक पुस्तकें, सेवकाल प्रमाण-पत्र, ग्रेच्यूटी चेक तथा मेडिकल कार्ड प्रदान कर सम्मानित किया।

डीएमएफटी और सीएसआर के तहत विभिन्न परियोजनाओं की हुई समीक्षा

रांची : उपायुक्त रांची राय महिमापत रे की अध्यक्षता में 31 जनवरी को डीएमएफटी एवं सीएसआर फंड की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। विकास भवन रांची सभागार में आयोजित बैठक में डीएमएफटी और सीएसआर फंड के उपयोग की समीक्षा की गयी। बैठक में विभिन्न विकास कार्यों के लिए तैयार की गयी योजना पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने जिले में 500 आंगनवाड़ी केंद्र को क्लिनिकल बेड से लैस करने के लिए अब तक किये गये कार्य की जानकारी ली। बैठक में उपविकास आयुक्त अनन्य मित्तल के द्वारा चल रहे सीएसआर परियोजनाओं जैसे एएनसी किट और एम्बुलेंस, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण की जानकारी दी गयी और आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त इंटीरियर क्षेत्रों में काम कर रहीं ए एन एम सेविकाओं को स्कूटी भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। डीएमएफटी एवं सीएसआर के अंतर्गत प्राप्त फंड को पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, वृद्ध एवं दिव्यांगजनों को सुविधाएं, स्किल डेवलपमेंट, सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई सहित ऊर्जा एवं वाटरशेड मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है।

सर्विसिंग अवधि में भी जरूरी मरम्मत नहीं हो पा रही कृषि बैंक के उपकरणों की

राजेश

रांची :मरम्मत के अभाव में राज्य में स्थापित कृषि बैंक के उपकरण अनुपयोगी होते जा रहे हैं। वांरटी अवधि में भी यंत्रों की सभी आवश्यक सर्विसिंग ससमय नहीं हो पा रही है। इसके मद्देनजर सरकार ने इसकी मरम्मत नवयुवकों से कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए उन्हें एक महीने का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक युवकों से आवेदन मांगे गये हैं।

जानकारी के मुताबकि राज्य में कृषक, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य सहायता समूहों को विगत कई वर्षों से कृषि उपकरण बैंक की स्थापना कर ट्रैक्टर, टैक्टर चालित यंत्र पावर टीलर, रीपर, पंप सेट, राईस हॉलर, कल्टीवेटर, डिक्स हैरो, सीड ड्रील कम फार्टिलाईजर इत्यादि कृषि यंत्र करिये पर उपलब्ध कराया जा रहा है। विभाग के संज्ञान में आया है कि मरम्मत के अभाव में अधिकांश कृषि यंत्र अनुपयोगी हो जा रहे है, क्योंकि संबंधित निर्माता और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मिस्त्री एवं मेकेनिक की उपलब्धता प्रखंड व ग्राम स्तर पर सुनिश्चित नहीं की जा पा रही है। विशेषकर वांरटी अवधि में भी पावर टीलर, रीपर, पंप सेट, राईस हॉलर, कल्टीवेटर, डिक्स हैरो, सीड ड्रील कम फार्टिलाईजर इत्यादि की सभी आवश्यक सर्विसिंग ससमय नहीं हो पा रही है।

कृषि विभाग के द्वारा अनुदान पर वितरित कृषि यंत्रों की विशेष मरम्मत, परिचालन एवं रखरखाव के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में तत्काल 160 नवयुवकों को निःशुल्क एक माह का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। यह प्रशिक्षण राज्य के ऐसे युवकों को दिया जाना है, जो आईटीआई, फीटर से पॉलिटेक्नकि, मैकेनिकल इंजीनियर या कृषि इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमाधारी या समकक्ष तकनीकी योग्यताधारी हो। प्रशिक्षण कार्यक्रम 6 फरवरी, 2020 से प्रस्तावित है। इसमें 30 युवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। चयनित प्रशिक्षणार्थी को उपलब्ध कराये गये उनके मोबाईल नंबर पर सूचित किया जायेगा। प्रशिक्षण रांची के हेहल स्थित ईटीसी परिसर में होगा। उक्त प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी के लिए मोबाईल नंबर 08789985308 या 08603229188 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

प्रशिक्षण लेने के इच्छुक प्रशिक्षणार्थी अपने जिला के भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी/जिला उद्यान पदाधिकारी से अनुशंसा कराते हुए सादे कागज पर अपने आवेदन में अपना नाम, पिता का नाम, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, मोबाईल नंबर, आधार संख्या, तकनीकी योग्यता के साक्ष्य प्रमाण पत्र, दो फोटो, के साथ अपना आवेदन समर्पित करेंगे। आवेदन को संबंधित जिला के उक्त पदाधिकारी द्वारा अपनी अनुशंसा करते हुए कार्यपालक निदेशक (कृषि अभियंत्रण), जेएएमटीटीसी, रांची, कृषि भवन, कांके रोड, रांची-834008 को डाक से या email - edjamttc@gmail.com के माध्यम से समय पर भेजना है।

रेलवे ने सेवानिवृति भुगतान किया

रांची : रेल मंडल पर कार्यरत विभाग के कुल 23 रेल कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए , इनमे एक अधिकारी चंदरेश्वर उरांव सहायक वाणिज्य प्रबन्धक तथा 22 कर्मचारी जिनमे रेल यूनियन मेंस काँग्रेस के मण्डल समन्वयक चंचल कुमार सिंह भी शामिल है, उन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात मिलने वाली सभी राशि का भुगतान किया गया।इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) एम एम पंडित ने सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात सुखद एवं स्वस्थ जीवन के लिए कामना की । सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के नाम भानु प्रताब सिंह परिचालन विभाग, अरुण कुमार परिचालन विभाग, अजित किशोर परिचालन विभाग, नारायण देवगम परिचालन विभाग, हीरालाल रजक परिचालन विभाग, मन बहाल कुजूर परिचालन विभाग, मादी वेंकट राव परिचालन विभाग, फाल्गुनी राम सनई परिचालन विभाग, एतवा काईनाथ हंस वित्त विभाग, चिमालाल कोंडाकुमार नारायण मूर्ति कार्मिक विभाग,विकाश कुमार भट्टाचार्जी विद्युत (परिचालन) विभाग, रामेन सोरेन विद्युत (सामान्य) विभाग, दिलेश्वर पांडे विद्युत (सामान्य) विभाग, राजेंद्र प्रसाद राजवंशी यांत्रिक विभाग, एलियाज़र नाईमन टोपनो यांत्रिक विभाग, राखा हरी गोप यांत्रिक विभाग, रवि मेटा यांत्रिक विभाग, रामपद महतो सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग, श्रीमती मीना सरेन मेडिकल विभाग, अशोक कुमार मिश्रा रेल सुरक्षा बल तथा रनथु महली रेल सुरक्षा बल। इस अवसर पर मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक देवव्रत बनर्जी, सहायक मण्डल कार्मिक अधिकारी मोहम्मद इबरार, सहायक विद्युत अभियंता (सामान्य) प्रभाकर राउत, सहायक मण्डल वित्त प्रबन्धक टी आर मीना तथा सहायक सुरक्षा आयुक्त ए के पांडे उपस्थित थे।

खेत लीज पर देने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड

राज्य सरकार ने वादा तो चकबंदी करने का किया था, लेकिन अब खेती की जमीन उद्यमियों को लीज पर देने का निर्णय ले लिया है।

एजेंसियां: उत्तराखंड सरकार ने राज्य की कृषि भूमि को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब कोई भी व्यक्ति या संस्था उत्तराखंड में 30 सालों के लिए जमीन लीज पर ले सकता है। सरकार का कहना है कि इससे उत्तराखंड वासियों को बंजर या खाली पड़ी जमीन से भी आमदनी होगी और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, लेकिन क्या ऐसा होगा? जानेमाने कृषि विशेषज्ञ देविंदर शर्मा कहते हैं कि अब तक उत्तराखंड में बटाई पर तो खेती की जमीन देते थे, लेकिन उद्योगपतियों को जमीन लीज पर देने का मतलब किसान अपनी ही जमीन का श्रमिक बन जाएगा। उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है, जो इस तरह का कदम उठा रहा है। देविंदर कहते हैं कि उत्तराखंड धीरे-धीरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग (ठेके पर खेती) की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अब तक के ज्यादातर अध्ययन से पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत उपयोगी साबित नहीं हुई है।वह सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहते हैं कि सरकार कॉर्पोरेट्स को पैसा देने को तैयार है, लेकिन किसान को देने को तैयार नहीं। कंपनियों के लिए सरकार निवेश कर सकती है, लेकिन किसान की सुविधा के लिए नहीं। यही वजह है कि अब किसान खेती करना ही नहीं चाहता। अपने बच्चों से खेती नहीं करवाना चाहता। फिर जमीन का क्या होगा। अब हम इस स्तर पर आ पहुंचे हैं कि बंजर खेत उद्यमियों को देने की नौबत आ गई है। वह हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देते हैं, जहां देश के सबसे समृद्ध गांव हैं। वहां के किसान भी खेती छोड़कर शहरों में बसना चाहते हैं। ऐसी मानसिकता बन गई है कि आप शहर के दो कमरों में रहना चाहते हैं लेकिन गांव के बड़े घर में नहीं। जबकि वहां सारी सुविधाएं मौजूद हैं। दरअसल सरकार चकबंदी लागू करने में असफल रही तो अब यह तरीका निकाला है। राजभवन से अनुमति मिलने के बाद 21 जनवरी को अधिसूचना जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भू-सुधार कानून-1950 में संशोधन के बाद यह व्यवस्था अब लागू हो गई है। इसके तहत किसान अधिकतम 30 एकड़ तक ज़मीन खेती, हॉर्टीकल्चर, जड़ी-बूटी उत्पादन, पॉलीहाउस, दुग्ध उत्पादन और सौर ऊर्जा के लिए किसी व्यक्ति, कंपनी या गैर-सरकारी संस्था को 30 वर्ष के लिए लीज पर दे सकता है। इसके बदले उसे किराया मिलेगा। जिलाधिकारी के मार्फत ये कार्य किया जा सकेगा। पर्यावरणविद जगत सिंह जंगली कहते हैं कि ये लोगों की गलती है, जिस जमीन पर हमारे पुरखों के फुटप्रिंट्स दर्ज हैं, वो लीज़ पर दी जा सकेगी। हमने अपने खेतों को बंजर छोड़ा। अगर खेती नहीं कर रहे थे तो पेड़ ही लगा देते। जंगली कहते हैं कि जिस ज़मीन को बंजर छोड़ हमारे लोग दिल्ली-मुंबई कूच कर गए हैं, महानगरों में बढ़ता प्रदूषण एक बार फिर उन्हें अपने पहाड़ों की ओर लौटने को विवश करेगा।

आज से दो पीढ़ी पहले तक यही खेत अन्न के भंडार थे। जिन पर कई पीढ़ियां निर्भर रहीं। जलवायु परिवर्तन ने भी पहाड़ की खेती को प्रभावित किया। समय से बारिश न होना, अत्यधिक बारिश होना, जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के चलते भी लोगों ने खेती छोड़ी। आज जंगली जानवर हमारे खेतों में घुस गया है। टिहरी के किसान विजय जड़धारी कहते हैं कि यह कदम पहाड़ के हित में नहीं है। सरकार लोगों को खेती के लिए प्रशिक्षित नहीं कर सकी। जब वे पलायन कर रहे थे और उन्हें इकट्ठा करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। जड़धारी पूछते हैं कि स्टार्टअप योजना, कौशल प्रशिक्षण केंद्र पर दी जा रही ट्रेनिंग का क्या हुआ। आप गांव के लोगों को सोलर पैनल लगाने की ट्रेनिंग देते। उन्हें एकजुट करके चाय बगान लगवाते। जड़धारी चंबा के आगे कौठिया क्षेत्र में बने बंदरबाड़े का उदाहरण देते हैं। जहां बंदरों को नसबंदी करायी जानी थी। लेकिन वहां सिर्फ इमारत खड़ी नजर आती है। पूरा बंदरबाड़ा सूना है। ऐसे ही खेती को नुकसान पहुंचा रहे कुछ जगहों पर जंगली सूअर को मारने के आदेश जारी किए। लेकिन क्या लोग इस काम को करेंगे। ये लोगों के बस की बात नहीं।

रिवर्स माइग्रेशन का उदाहरण बने पौड़ी के किसान सुधीर सुंद्रियाल कहते हैं कि स्थानीय लोग भरोसा करने को तैयार नहीं है कि इन बंजर खेतों में अब गोभी, ब्रोकोली के फूल दिख सकते हैं। पौड़ी के पोखड़ा और एकेश्वर ब्लॉक में कई किलोमीटर तक बंजर ही बंजर जमीन दिखती है। इस बंजर को आबाद करने की ताकत यहां के स्थानीय आदमी में नहीं है। इसलिए मौजूदा हालात में ये मॉडल जरूरी है।

BOOK INDIA
DEALS IN SCHOOL BOOKS & STATIONARY
BRANDED BOOK REASONABLE PRICE
LEADING PUBLISHERS
- Top High Quality Books
- C.B.S.E., NCERT,ICSE & JAC Board
- 365 Days Services

SPECIALIST IN Pvt. School Books/Play School Books/Childrens Books

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पुस्तकें उपलब्ध

Sahay Compound, St. Anne's Girls School Lane, Tharpakhna, Ranchi Ph. : 9199365691,7050112727,0651-6522703

फोटो न्यूज

गुंगु पते की टोपी : पुरानी परंपरा को बचाने को प्रयासरत है हेमा

सिदाम

दशम फ़ॉल की सीढ़ी पर एक लड़की आदिवासी परिधान में लाल पाड़ साड़ी और माथे पर गुंगु पते की टोपी पहन रखी है। अपने स्टॉल में गुंगु पते की टोपी बेच रही है।सैलानी उनके यहां से टोपी खरीद भी रहे हैं तो कुछ सेल्फ़ी के लिए भाड़े पर टोपी ले रहे हैं। एक टोपी की कीमत 60 रुपये है। सेल्फ़ी के लिए टोपी 10 रुपये में भाड़े में दी जाती है।पूछने पर अपना नाम हेमा कुमारी बताती है।नजदीक के ही हाँजेत गांव की रहनी वाली है। फ़िलहाल रांची में रहती है।टेलिकॉलिंग का जॉब करती है। छुट्टियों में गांव आती है। पिताजी के द्वारा बनाए गए गुंगु पते की टोपी को बेचती है और पिताजी के सपने को साकार करने की कोशिश कर रही है।

अपने भाई के साथ स्टॉल में बैठी हेमा बताती हैं कि पिताजी रायसिंह मुंडा गांव के ही स्कूल में पाय शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। जब भी फ़ुर्सत मिलती गुंगु पते की टोपी बनाते हैं। वे चाहते हैं कि अपने आस-पास की चीजों को हुनर के साथ तराशा जाए तो उसे आकर्षण का केंद्र बनाया जा सकता है।गुंगु पते की टोपी भी उनमें से एक है। इस पते से पुराने जमाने में धुप, बरसात से बचने के लिए लोग टोपी बना लेते थे। बरसात और ठण्ड से बचने के लिए कोट के रूप में भी बना लेते थे। आज भी मंच पर लोगों को सम्मान में गुंगु पते की टोपी पहनाया जाता है।गुंगु पता पेड़ों में लता के रूप में विकसित होता है। पिताजी चाहते हैं कि पुरानी परम्परा को मॉडर्न युग के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाए और उसके लिए मेहनत भी करते हैं। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। कभी रोजगार की तलाश में विदेश जाने की चाह रखने वाले पिता रायसिंह मुंडा अपने हुनर से एक मिशाल पेश करना चाहते हैं कि अपने आस-पास भी रोजगार किया जा सकता है। वे बांस से जुडी कई जरूरी सामान भी बना कर बेचते हैं उससे भी आमदनी होती है।हेमा कुमारी मुंडारी, सादरी, हिंदी ,अंग्रेजी भाषा की जानकारी है।अभी वह गुंगु पते की टोपी तो बनाना नही सीखी पर बेचने में अपने पिताजी का सहयोग कर रही है।

हल्दी की खेती से किसानों की जेब होगी 'हेल्दी'

राजन कुमार

हल्दी हमारे रसोई का प्रमुख मसाला है। लेकिन हम सब इसे सिर्फ मसाले के तौर पर उपयोग नहीं करते हैं बल्कि चोट लगने, दर्द पीड़ा, खांसी के इलाज से लेकर शादी विवाह या मांगलिक कार्यों में भी जरूर उपयोग करते हैं। हल्दी हम भारतीयों के घर की जरूरत है।

देश में गन्ने की खेती के लिए मशहूर पश्चिमी यूपी में किसान अब औषधीय फसल हल्दी की खेती पर हाथ अजमा रहे हैं। पहली बार जिले में बड़े पैमाने पर हल्दी की फसल उगाई गई है। हल्दी की फसल मुनाफे का सौदा साबित हुई तो इसका रकबा बढ़ना तय है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि किसान और खेत दोनों के लिए हल्दी की खेती संजीवनी साबित हो सकती है।

दरअसल, औषधीय गुणों वाली हल्दी को लोग दैनिक जीवन में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। मुकंदपुर गांव के किसान बिजेंद्र, लोकेंद्र और कूड़ी गांव

के किसान संदीप ने बताया कि हल्दी की खेती की शुरूआत की है। लाभ मिलने का अनुमान है। सब कुछ ठीक रहा तो अगले वर्ष इस फसल का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे। प्रगतिशील किसान धर्मेंद्र कुमार बताया कि हल्दी गुणकारी होती है। चोट, मोच, कटने और जलने पर औषधि के रूप में इसका लोग इस्तेमाल करते हैं। सब्जी कोई भी हो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। इसको देखते हुए हल्दी की खेती करने की योजना की थी। क्षेत्र के किसानों को भी इससे जोड़ा गया है। डौला, शेरपुर, लुहारा सहित अन्य गांवों में किसान इसकी खेती कर रहे है। एडीओ कृषि महेश कुमार खोखर ने बताया कि सहफसली खेती के तहत किसान हल्दी की खेती को अपना सकते हैं। शुरूआत अच्छी हुई है। फसल तैयार होने पर मुनाफा मिलेगा। वर्तमान में 100 बीघा से ज्यादा में हल्दी की बुआई किसानों ने की है।

एंटीबायोटिक है हल्दी, निकाला जाएगा तेल

जिस तरह से लेमन ग्रास का तेल निकाला जाता है, उसी प्रकार अब हल्दी से भी तेल निकालने का काम किया जाएगा। क्योंकि बाजार में इसकी मांग है। मई-जून माह में होती हल्दी की बुवाई होती है।एडीओ कृषि महेश कुमार खोखर ने बताया कि हल्दी की फसल को बरसात के सीजन से पहली मई-जून माह में इसकी बुवाई करते है। छह माह में फसल तैयार हो जाती है। जिसको बाजार में बेचने पर अच्छा मुनाफा किसान कमा सकते है। गन्ने के साथ सहफसली खेती कर आय में दोगुनी कर सकते है।

नागपुरिया : जनसंपर्क भाषा कर मान मिलेक चाही

बलदेव शर्मा

कोनोवे भाषा के अभिव्यक्ति कर बढ़िया माध्यम मानल जायला । हमारे कर छोटानागपुर में भी दर्जनों भाषा है । इकर परमान दैनिक जीवन में गांव गली और मुहल्ला में बोलते बतियाते देखल आउर सुनल भी जायला। जेकर में नागपुरिया कुडुक, मुंडारी , खड़िया, हो , करमाली, पंचपरगनियाआउर खोरठा प्रमुख हय। मुदा इस सब भाषा में सबसे बेसी छोटानागपुरिया भाषाकर प्रचलन आहे। येहे वास्ते छोटानागपुर में नागपुरिया बोली के सबसे बड़का जनसंपर्क भाषा कर मान मिलेक चाही। लेकिन इकर केखों चिंता नखे इहां तक कि ई भाषा कर मजबूती और विकास लागीन जे पहल आउर परयास होना चाही नइ होलकर। कुछ पहल करल जाहे उके हामरे नाकाफी कईह सकीला। काहे कि नागपुरिया कर पढ़ाई स्कूल से शुरू करना रहे। लेकिन नागपुरिया कर पढ़ाई कालेज शुरू करल जायहे। हालांकि नागपुरिया कर बहुत पहले कौनो लिपि आउर साहित्य नइ रहे । मुद्दा सैकड़ों बरीस पहिले से ही नागपुरिया कवि आपन लोक संस्कृति और सेबेर कर घटनाक्रम के लिपिबद्ध करेक ले शुरू करलयं कर टूटल फुटल सबूत हय कहनी आउर कविता कर रूप में। उ कविता मनके गीत कर माध्यम से परचार परसार करत करलयं। जेकर में महेश राम घासीराम द्रृगपाल राम देवघरिया जैसन कई नाम के याईद कइर सकीला । इस कवि मनकर कविता कर संग्रह करल जाय तो नागपुरिया भाषा वास्ते मील कर पत्थर साबित होइ। इकर बाद कर काल में तो ढेईर कवि मनकर नाम लेवल जाय सकेला। मुदा सबकर नाम लेवेक एखन जरूरी नखे। फिर भी लोहरदगा जिला कर बदला गांव कर संत कुमार पाण्डेय जी कर योगदान के याईद ना करू तो नाइंसाफी होवी। काहे कि नागपुरिया भाषा कर पहिला व्याकरण पाण्डेय जी ही लिख रहंय।

जे नागपुरिया भाषा आउर साहित्य ले रीढ़ कर काम करलक। वर्तमान में नागपुरिया भाषा कर विकास लागिन लेखक आउर कवि कर साथ कुछ शिक्षक एकता कर परयास शुरू कइर हयं । इमनक इ भाषा में पत्रिका छापेक

वायुमंडल को प्रदूषित कर रही हैं लाल सागर से निकलने वाली गैसें:

एजेंसियां: एक अध्ययन में खुलासा हुआ है कि लाल सागर के नीचे से निकलने वाली हा-इड्रोकार्बन गैसें कुछ बड़े जीवाश्म ईंधन (फॉसिल फ्यूल) निर्यातक देशों के उत्सर्जन के बराबर की दर से वायुमंडल को प्रदूषित कर रही हैं।पानी में इन गैसों का रिसाव मिस्र, इज़राइल, जॉर्डन और सऊदी अरब सहित कई देशों के रिसॉर्ट्स और बंदरगाहों से हो रहा हैं। ये गैसें औद्योगिक शिपिंग से होने वाले उत्सर्जन के साथ घुल जाती हैं और वे प्रदूषण में बदल जाती हैं। जो इंसानों के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं।मिडिल ईस्ट में दुनिया के आधे से अधिक तेल और गैस भंडार हैं। वहां तेजी से जीवाश्म ईंधन का दोहन होता है, जिसके कारण इस क्षेत्र से भारी मात्रा में गैसीय प्रदूषक वायुमंडल में फैल जाते हैं।

गेहूं की पैदावार कम कर देते हैं खरपतवार

डॉ. विनोद शर्मा

गेहूं हमारे देश की मुख्य फसल है, परंतु देश में गेहूं की पौष्टिकता आस्ट्रेलिया अमेरिका की गेहूं से निम्न है। गेहूं फसल को हानि पहुंचाने वाले विभिन्न कारकों में सबसे अधिक हानि खरपतवार पहुंचाते हैं। ये अवांछनीय पौधे गेहूं में उगकर पोषक तत्वों, नमी, वायु, प्रकाश व स्थान आदि के लिए स्पर्धा कर फसल को कमजोर बना देते हैं। हानिकारक कीटों व बीमारियों का आश्रय स्थल बनकर फसल की उपज व गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। गेहूं की फसल में खरपतवारों से होने वाले नुकसान को 25-75 प्रतिशत तक आंका गया है। किसान प्रायः अपनी फसल में निकलने वाले खरपतवारों को जानवरों के चारे के लिए उपयोग करने के लिए समय पर इनका नियंत्रण नहीं करते व इससे उनकी उपज में भारी कमी आ जाती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए गेहूं की प्रारंभिक अवस्था, जो कि 30-45 दिन आंकी गई है अति महत्वपूर्ण है। इसमें इनका निदान किसी भी विधि से अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा फसल के उत्पादन में कमी आती है। गेहूं में खरपतवारों की रोकथाम के लिए किसान कई तरीके अपना सकते हैं। इनमें दवाइयों का छिड़काव से लेकर निराई-गुड़ाई से भी खरपतवार पर अंकुश लगाया जा सकता है। **यह सावधानियां बरतें किसान** ●खरपतवारनाशी का प्रयोग करते समय खेतों में नमी का होना आवश्यक है। ●खरपतवार के प्रकार और संख्या को ध्यान में रखकर खरपतवारनाशी का चुनाव करें। ●छिड़ककाव करते समय खरपतवार व फसल की अवस्था का ध्यान रखें। ●छिड़काव फ्लैट फैन नोजिल लगे पंप से ही करें। ●खरपतवारनाशी का सही मात्रा, सही समय एवं उपयुक्त तकनीक से छिड़काव करें। ●गेहूं में खरपतवार निवारण के लिए खरपतवारनाशी को अदल-बदल कर उपयोग में लाएं।

हवा साफ करो तब वोट देंगे

एजेंसियां :दिल्ली में 8 फरवरी को चुनाव हैं। इसबीच कई नागरिक समूह मिलकर सभी राजनीतिक पार्टियों और आम लोगों के बीच संवाद स्थापित कर रहे हैं। नेताओं से स्वच्छ हवा का वादा दिलवाकर उनकी जवाबदेही तय की जा रही है। माई राइट टू ब्रीथ के तहत यह नागरिक आंदोलन किया जा रहा है। यह दिल्ली की 15 विधानसक्षा क्षेत्रों के टाउन हॉल में होगी। इनमें मंगोलपुरी, आरकेपुरम, रिठाला, द्वारका, बदरपुर, विकासपुरी, पटपड़गंज, किरारी, लक्ष्मीनगर, नांगलोई, रोहिणी, घोंडा और कालकाजी शामिल हैं। संगठनों की ओर से कहा गया कि राजधानी दिल्ली दुनिया में सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल है। वहीं महीन कणों वाले पार्टिकुलेट मैटर के प्रदूषण के चलते रोजाना करीब 80 लोगों की मौत होती है।

दशम जलप्रपात में टुसू मेला का हुआ आयोजन

सिदाम

रांची/बुण्डूः गणतंत्र दिवस के मौके पर दशम जलप्रपात में टुसु मेला का आयोजन किया गया।हर साल लगने वाले इस मेले में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए।आसपास के गांव से कई टीम ढोल-नगाड़े के साथ शामिल हुई।चौड़ल टीम के द्वारा टुसु गीत पर पारम्परिक नृत्य का प्रदर्शन किया गया।मेले में शामिल सभी चौड़ल टीम को पुरस्कृत किया गया।मेले में पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग के द्वारा नृत्य के माध्यम से झारखण्ड की संस्कृति को दिखाने का भी प्रयास किया गया। पर्यटक मित्र पतरासोरा, शिवनाथ मुंडा सहित सभी पर्यटक मित्र के सहयोग से इस मेले का सफल आयोजन हुआ।

मेले में ग्राम कमिटी के अध्यक्ष सह पर्यटन मित्र सुरक्षा प्रभारी योगेश्वर अहीर, दशम थाना एसआई अनुशेक कुमार, एएसआई चन्द्रनाथ ओरांव मौजूद रहे।

बहुत अच्छी है किसान रेल की योजना

एजेंसियां :भारत जैसे देश में अगर ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि फलां जिले मेंया राज्य में किसानों ने सड़क पर ही टमाटर या आलू फेंक दिये। सड़कों पर ही दूध बहा दिये। अपने उत्पाद की सही कीमत न मिलने के कारण किसान उसे मंडियों में ही छोड़ कर चले आये? क्योंकि उसे ढो कर घर लाने में जो खर्च थे वो उनकी फसल की कीमत से ज्यादा थे। ऐसे में किसान रेल की योजना कुछ उम्मीदें जता रही हैं? वित्त मंत्री ने अपने भाषण में इस बात की घोषणा की कि दूध, मांस और मछली जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए ऐसी ट्रेन चलाई जाएगी जो कम से कम स्थानों पर रुकेगी। इसे पीपीपी मॉडल के तहत भारतीय रेलवे किसान रेल के नाम से चलाएगा। ध्यान रहे कि भारतीय रेलवे को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। बजट में पहली बार रेल किसान की बात कही गई है। हालांकि इस संबंध में देखने वाली बात होगी कि इस स्टोरेज का खर्च किसान वहन करने की स्थिति में होगा क्या? इस संबंध में बुलंदशहर के किसान छोटेलाल चौहान कहते हैं कि पहले तो यह देखना होगा कि किसान अपना सामान रेलवे स्टेशनों तक पहुंचाने की व्यवस्था होगी और फिर सही है कि जब तक किसानों की आय में बढ़ोतरी के उपाय नहीं किए जाएंगे तब तक इस प्रकार की जितनी भी ट्रेने सरकार चला ले किसान को लाभ होने से रहा। वह कहते हैं कि सरकार की पहल अच्छी है लेकिन इस पहल के आसपास की चीजों को भी सरकार दुरूस्त करना होगा। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि चार रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और 150 यात्री गाड़ियों को निजी व सरकारी भागीदारी से चलाया जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि अब तक केवल एक स्टेशन यानी भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन इस मॉडल के आधार पर तैयार किया गया था। अब इनकी संख्या बढ़ाकर चार की गई है। चूंकि पिछले बार जब इसकी घोषणा की गई थी तो बताया गया था कि इसका लीज टाइम 45 साल होगा। ऐसे में बड़ी कंपनियों ने इसके लिए निविदाएं नहीं भरीं। इस संबंध में रेलवे वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंदर गुप्ता कहते हैं कि इससे रेलवे ने इस बार लीज की समयाअवधि अब 99 साल कर दी है। ऐसे में उन्हें उम्मीद होगी कि अब बड़ी सख्या में कंपनियां टेंडर भरेंगी।

प्रदूषण से पौधे जल्दी मुरझाते हैं

वाहनों से हो रहे प्रदूषण और कुछ विशिष्ट गैसों में कमी, पौधों के विकास में मददगार हो सकती है। यह न सिर्फ पौधों को जल्द विकसित होने में मदद करती है। बल्कि साथ ही उन्हें अधिक कार्बन अवशोषित करने के लायक भी बनाती है। गौरतलब है कि ओजोन का उत्सर्जन सीधे तौर पर नहीं होता है। मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों और नाइट्रोजन ऑक्साइडों के आपस में जटिल रासायनिक प्रतिक्रिया करने के कारण वायुमंडल में ओजोन का निर्माण होता है। यही ओजोन पृथ्वी की सतह पर प्रकाश संश्लेषण को सीमित कर देती है, जिससे पौधे प्रचुर मात्रा में भोजन नहीं बना पाते । परिणामस्वरूप उनके बढ़ने की क्षमता घट जाती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इन गैसों के उत्सर्जन में कमी करके जलवायु परिवर्तन को सीमित किया जा सकता है। यह अध्ययन एक्सेटर विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। जोकि अंतराष्ट्रीय जर्नल नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित हुआ है।

अध्ययन के अनुसार इन गैसों में 50 फीसदी की कटौती ने केवल जलवायु परिवर्तन को रोकने में मददगार हो सकती है। साथ ही यह पौधों को अधिक मात्रा में कार्बन सोखने में भी मदद करती है। यह गैसें मुख्यतः सड़क परिवहन और ऊर्जा उत्पादन, कृषि, आवास, उद्योग, वेस्ट/ लैंडफिल और शिपिंग, इन सात स्रोतों से सबसे अधिक उत्सर्जित होती है। एक्सेटर विश्वविद्यालय से सम्बंधित प्रोफेसर नादिन उंगर ने बताया कि, "जमीन पर मौजूद इकोसिस्टम हर साल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का करीब 30 फीसदी हिस्सा स्टोर कर लेता है। जिसके कारण वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि घट जाती है।" लेकिन ओजोन के बढ़ते प्रदूषण के कारण पौधों द्वारा कार्बन कैप्चर करने की गति में कमी आ रही है। शोध से पता चला है कि पूर्वी अमेरिका, यूरोप और पूर्वी चीन में पौधों की उत्पादकता तेजी से कम हो रही है। जहां ओजोन प्रदूषण काफी ज्यादा है। अनुमान है कि इन क्षेत्रों में पौधों की वृद्धि पर हर साल करीब 5 से 20 फीसदी का असर पड़ रहा है। अध्ययन के अनुसार इन गैसों में 50 फीसदी की कटौती का लक्ष्य बड़ा तो है पर नामुमकिन नहीं है। जैसे की कुछ उद्योगों ने पहले भी ऐसा करके दिखाया है। प्रोफेसर उंगर ने बताया कि वाहनों और ऊर्जा उत्पादन से हो रहे प्रदूषण में कटौती करना ओजोन से निपटने का सबसे बेहतर विकल्प है। साथ ही यह पूर्वी चीन, यूरोप, पूर्वी अमेरिका और दुनिया भर में उत्पादकता को हो रहे नुकसान को सीमित करने का प्रभावी उपाय है। यह कार्बन में कमी लाने का एक प्राकृतिक उपाय है। साथ ही यह जीवाश्म ईंधन से हो रहे उत्सर्जन में कमी करने, वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में अहम भूमिका निभा सकता है।

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक मनोरंजन सिंह द्वारा प्रकाशित तथा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित और सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2, टीवीएस गली, रातू रोड, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com.☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।